Shortage of Power in Gujarat

1263. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will. the Minister of POWER b$_e$ pleased to state:

(a) whether the power supplied to Gujarat falls short of its requirement;

(b) if so, what is the requirement and supply of power to Gujarat during each of the last three year;

(c) whether the availability of power in Gujarat is less in comparison to other States; and

(d) if so, what steps are being taken by Government to treat Gujarat at par with other States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER (SHRI KALP NATH RAI): (a) and) (b) Power supply position in Gujarat during last three years is as follows:

Year J	Require-meat (MU)	Availability (MU)	Shortfall	
			MU	Percentage
1989-90	21565	20823	742	-. 3' 4
1990-91	23305	22358	947	41
1991-92	25505	24417	1088	,4.3,

MU— Million Units

(c) Availability of power in Gujarat has been more than the National average. All-India shortfall in power supply during the year 1988-80 and 1990-91 was 7.9 per cent while in 1991-92 it was 7.8 per cent which is more than the shortfall in Gujarat.

(d) Various measures taken to improve the availability of power in Gujarat include maximising the generation from the existing generating stations, implementation of Renovation and Modernisation programme of generating stations, reduction in Transmission and Distribution losses effective load management and conservation of energy etc. Assfetance is also made available to Gujarat from the neighbouring systems whenever system conditions are conducive to such transfer.

जल विद्युत के उत्पादन में कमी

1264. श्री विनोद शर्मा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1968 में जल विद्युत क्षेत्र में विद्युत उत्पादन देश के कुल विद्युत उत्पादन का 45.86 प्रतिशत होता था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि 1992 में यह घटकर लगभग 28 प्रतिशत रह गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) मार्च, 1992 तक कुल कितनी जल विद्युत परियोजनायें सरकार के पास विभिन्न स्तरों पर स्वीकृति के लिये लंबित पड़ी थीं तथा इसमें कितनी उत्पादन क्षमता की परिकल्पना की गई है ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) देश के समग्र विद्युत उत्पादन में जल विद्युत उत्पादन

की मात्रा 1966 और 1992 में क्रमशः 45.68 प्रतिशत और 25.32 प्रतिशत थी । जल विद्युत उत्पादन में गिरावट का मुख्य कारण इस अवधि के दौरान ताप विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित किये जाने पर अधिक जोर दिया जाना रहा है ।

(घ) मार्च, 1992 तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, कुल मिलाकर 7832 मेगावाट क्षमता की 42 जल विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु निवेश संबंधी स्वीकृति के लिए तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर चुका है ।

विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

1265. **श्री विनोद शर्मा :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी संस्थाओं के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करके देश में विद्युत उत्पादन करने के संबंध में समझौते किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कुल कितने उद्यमों के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ग) इन संयुक्त उद्यमों के माध्यम से देश में कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्णय किया गया है तथा यह लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लिया जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत दर में 12 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि करने का सरकार का निर्णय

1266. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विद्युत दर में 12 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि करने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि विद्युत की दरों में वृद्धि के परिणाम-स्वरूप औद्योगिक उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हो जायगी तथा इससे देश के निर्यात पर भी प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अनुसार राज्य बिजली बोर्डों के टैरिफ की संरचना इस प्रकार की होनी चाहिये कि वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित निवल परिसंपत्तियों पर न्यूनतम सांविधिक 3% का अधिशेष अर्जित किया जाना सुनिश्चित किया जा सके । टैरिफ का निर्धारण करना संबंधित बोर्ड/राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है ।

(ग) और (घ) विद्युत टैरिफ में वृद्धि किये जाने के कारण औद्योगिक उत्पाद की लागत पर जो प्रभाव पड़ेगा यह भिन्न-भिन्न राज्य के लिये भिन्न-भिन्न होगा, क्योंकि अन्य निवेशों में विद्युत ही एक निवेश होता है और ऊर्जा सघन उद्योगों को छोड़कर सभी लागत घटकों में इस की औसत मात्रा 5% से 6× तक होती है । अतः लागत आधारित विद्युत टैरिफ से औद्योगिक उत्पाद और निर्यात सामग्री की लागत में किसी प्रकार की वृद्धि होने की संभावना नहीं है ।

देश में "प्लांट लोड फैक्टर" की दर

1267. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री रणजीत सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में "प्लांट लोड फैक्टर" की दर संतोष-जनक नहीं है ;